[Shri Samar Guha]

he was the Supreme Commander of the INA, the head of the Provisional Government of Free India, there was not a single Bengali in his personal or household staff. Every one of them naturally came from the other parts of the country because he did not divide one part from the other. India as a whole was his motherland. He never used the world "India" to mean a country; whenever he mentioned India he referred to it as motherland. *janani, janmabhumi. Therefore, to* him, India was a concept, much more than a geographical entity. It was something else to him. Whoever came from any part of the country was his brother, as any brother from Orissa or Bengal.

I particularly mention that the Bengal Government has done a wrong and an injustice by declaring 23rd January as an official holiday. They should have made a demand: they should have waited; they should have struggled; they should have made a demand: they should have tried to influence the Government of India that until and unless the Government of India declared 23rd January as a national holiday, no State, what to speak of Bengal, can separately declare 23rd January as an official holiday.

The question will naturally arise why only the birthday of Netaji Subash Chandra Bose should be observed as a national holiday. During the freedom struggle of our country, there had been many great men. India had produced many great leaders who had made immense contribution to the freedom struggle of our country. Why not the birthdays of all great men should be observed as national holidays? This is a very pertinent question, a very reasonable question. Besides a national holiday that is being observed on the birthday of the Father of the Nation, why I want that the birthday of Netaji should be observed as a national holiday. I have to justify it, as I used the word, I use it again, historically, philosophic and politically too.

With this poser, why the birth of Netaji should be observed a national holiday, I will plead you, Sir, next time that at least I have to take enough time to ju the reason for my pleading that birthday of our greatest hero of freedom struggle should be obse as a national holiday.

With these introductory remark just postpone my speech to the day.

MR. CHAIRMAN: You may cont your speech on the next day.

17.33 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMIT

NINTH REPORT

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I to present the Ninth Report of Business Advisory Committee.

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF LABOUR AND P LIAMENTARY AFFAIRS (DR. R KIRPAL SINHA): Mr. Chairman, about the Report which has been sented, I have to make a submiss

As agreed to in the Committee, discussion on the recent cyclone hit the Southern parts of the cou and relief measures will be taken betweeen 5 P.M. and 7 P.M. on T day, the 6th December, 1977. Co quently, the discussion on the Fara Agreement which was proposed to put down for that day will now taken up on the 15th December, I I hope, the House will agree with consequential re-adjustment of b ness.

17.35 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSIO

DEVELOPMENT OF FORESTS

MR. CHAIRMAN: We now take the Half-An-Hour Discussion. Yuvraj.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill.....

MR. CHAIRMAN: You cannot move now.

SHRI K. LAKKAPPA: I am only introducing the Bill....

MR. CHAIRMAN: Now we have the Half-an Hour Discussion. Mr. Yuvraj.

SHRI K. LAKKAPPA: I am only introducing the Bill. The discussion of that may be taken up later.

MR. CHAIRMAN: As per rules, you cannot.

SHRI K. LAKKAPPA: Under what rule, Sir?

MR. CHAIRMAN: Two things cannot be taken up together. You are a senior parliamentarian.

SHRI K. LAKKAPPA: That is why, Sir, I am asking for the rule. There are no rules to say that I should not introduce this now. My Bill has been pending for a long time.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have called Mr. Yuvraj.

SHRI K. LAKKAPPA: You have not told me, Sir, under what rule I cannot introduce.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You are a senior parliamentarian. Two things cannot be taken up together. Mr. Yuvraj.

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति महोदय, आधे घंटे की चर्चा के लिए जो समय निर्धारित है उसका सम्बन्ध वन के स्टाफ से है । 14 नवम्बर, 1977 को जो तारांकित प्रश्न पूछा गया था उस सिलसिले में जो उत्तर सरकार ने दिया था वह बहुत ही अस्पष्ट, भ्रामक और तथ्यों मे परे था, इसलिए जरूरत पड़ी कि दोबारा मैं उस सिलसिले में चर्चा करूं ।

आप देखें कि 16 अगस्त, को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव ने एक सेमिनार बुलाया था । उस सेमिनार में उन्होंने बतलाया था कि जो वन के उत्पादन या फारेस्ट्री के लिए दस करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था उस में बेकार भूमि, वैरेन लैण्ड या ग्राम पंचायतों की जमीन के लिए भारत सरकार ने पांच करोड़ रुपए रखा था और जो वन उजाड़ा गया था, दोबारा उस वन को बनाने के लिए, दोबारा वहां वृक्षारोपण करने के लिए पांच करोड़ रुपये रखा था । इस तरह कुल दस करोड़ रुपए का उपबन्ध किया गया था और यह बतलाया गया था कि इससे स्थानीय लोगों को यानी जो ग्रामीण लोग वहां बसते हैं या जो स्किल्ड हैं, कार्यकुशल है उनको रोजगार मिलेगा । लेकिन आप देखेंगे कि आज शनै-शनै. वन की वृद्धि होने के बजाय उसका बड़ा नुकसान हो रहा है । वन उत्पादन या वन का विकास भारत की अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रखता है । उद्योग के काम में, प्रति रक्षा के काम में, संचार और रेल के काम में इसका उपयोग होता है । यह दु.ख की बात है कि हम कागज, पेपर बोर्ड या न्यूजप्रिंट आदि करोड़ों रुपए का आज आयात करते है । तीस वर्षों के बाद भी हम सक्षम नही हो पाये कि जो हमारी आवश्यकता है उसे अपने यहां बना सकें । जैसे कागज के बिना हम काम नहीं चला सकते, वह कागज महीने में करोड़ों रुपए का हमें बाहर से मंगाना पड़ता है ।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि किस तरह से बेकार भूमि और पंचायत की भूमि मे जो वन लगाने की योजना हैं उसमें दिन व दिन गिरावट आई है । वन के बिना जिस तरह मे वर्षा नही हो सकती है, वन नियंत्रण के अभाव में बाढ़ नियंत्रण का काम नहीं

[श्री युवराज]

हो सकता है, वन के अभाव में जो इमारती लकड़ी प्राप्त होती थी वह प्राप्त नहीं हो पा रही है, औद्योगिक लकड़ी जो प्राप्त होती थी उसका भी अभाव है, इस प्रकार से वन के अभाव में इस देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रहार हुआ है जो कि हमारी अव्यवस्था का द्योतक है ।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि यहां पर जो एस्टीमेट्स कमेटी की 65वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें सरकार के निकम्मेपन की चर्चा की गई थी । उस रिपोर्ट में यह कहा गया :

The Committee are greatly concerned that no concrete steps have been taken so far. The very first step suggested in the First Five-Year Plan document (that an immediate reconnaisance survey of wasteland be made so as to know how much wasteland would be available in any State and what proportion of wasteland would be suitable for raising plantation) has not been included in the Fifth Five-Year Plan.

यानी करीब-करीब 15–16 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ । हमारे देश में कितनी ही जमीन वेस्टलैण्ड है जहां पर हम वन लगा सकते हैं । वहां पर छोटे बड़े जंगल लगाने का काम किया जा सकता है । हमारे पास उसकी कोई फीगर्स तक उपलब्ध नहीं थी। दोबारा फिर एक प्रयास किया गया और आप देखेंगे कि सबसे पहला जो वन का कानून था वह 1927 में बना था । दूसरी दफा 1952 में वन के लिए एक पालिसी बनाई गई । इस तरह से आप देखें कि इस काम में कितनी शिथिलता थी । वन के बिना आज हमारे जो उद्योग हैं वे चौपट हो रहे हैं । वन के बिना हमारी आर्थिक व्यवस्था दिन प्रति दिन गिरती जा रही है । इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, इस प्रकार की तमाम चीजें हम वहां से प्राप्त करते हैं । आजकल रेलवे एक्सीडेन्टस की बड़ी चर्चा हो रही है लेकिन आपको पता होगा इस देश में रेलवे लाइनों के लिए जो स्लीपर्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, रेलवे लाइन के नीचे जो लकड़ी डाली जाती है उसके लिए भी इतनी लकड़ी नहीं है कि सरकार स्लीपर्स की व्यवस्था कर सके । इसका मतलब यह है कि वनों का दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है । वनों में दिन प्रति दिन गिरावट आती जा रही है ।

इस सम्बन्ध में मेरे पास जो कुछ फीगर्स हैं उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । इस देश में वनों का टोटल एरिया 746 लाख हेक्टेयर है जो कि कुल क्षेत्र का 22.7 प्रतिशत है । हमारी योजना थी कि हम 33.3 प्रतिशत हिस्से में वनों का विस्तार करेंगे लेकिन वह नहीं हो सका । वनों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए । वना के लगाने के नाम पर, पौधे लगाने के नाम पर, लकड़ी के उत्पादन के नाम पर और वनों की रक्षा करने के नाम पर नौकरशाही में करोड़ों रुपए बर्बाद किए लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला ।

वनों के आस पास आदिवासी लोग रहते है, वनवासी लोग रहते हैं लेकिन आप देखें कि बिहार के हजारीबाग जिले में क्या होता है और मध्य प्रदेश के जंगलों के पास की बस्तियों में क्या होता है ? गिरिडीह में बेचारे आदिवासियों की मौरूसी पैतृक जमीन है, उनकी एन्सेस्ट्रल प्रापर्टी

है जिनके पास 1954 का रिकार्ड है, जब जमींदारी उन्मूलन हुआ उसका जिनके पास रिकार्ड है, रसीद और पर्चे हैं वहां पर वन विभाग के अधिकारी पांच हजार से अधिक मुकदमें छोटे-छोटे किसानों पर चला रहे हैं। आज वहां पर पांच हजार मुकदमेंसबजुडिस हैं । इस प्रकार से छोटे किसानों को परेशान किया जाता है । वे कोर्ट में जाते हैं तो उनके केस कम्पाउन्ड करा दिए जाते हैं। उन से रुपया लिया जाता है, उनकी मौरूसी जमीन से उनको वंचित किया जाता है । आज "वन सीमा" के नाम पर जो शोषण होता है—बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, उस के कारण छोटे-छोटे किसान तबाह हो रहे है । इसलिये मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जो असंतोष फैला हुआ है, वह किन लोगों में है ? उन लोगों में है जो सबसे वीकर सैक्शन है, जो आज की सुविधाओं से वंचित है, जो आज की टैकनोलाजी की सुविधा से वंचित है, जो वैज्ञानिक सुविधा से वंचित है, जो आज की सभ्यता से दूर है, जो भूखे रहते हैं, जो खेती पर काम करते हैं और जो केवल डेढ़ या दो रुपये रोज की मजदूरी पर काम करते हैं—वे बेरोजगार आदिवासी आज बहुत परेशान हैं और आपके वन के अधिकारी उनको तबाह और परेशान करते हैं । आप इसकी जांच करवाइये कि गिरिडीह, हजारी-बाग, संथाल परगना—तमाम दक्षिणी बिहार में वहां के स्थानीय किसानों को—छोटे-छोटे किसानों को—किस तरह से तंग और तबाह किया जा रहा है । ये हजारों मुकदमे जो पेंडिंग हैं, उनको आप वापस लें और उन किसानों की मौरूसी जायदाद और पैत्रिक सम्पत्ति पर जो कब्जा कर लिया गया है, उसको उन्हें वापस दिलाया जाये । आज जनता पार्टी के नाम पर यह कलंक है—उन लोगों को जनता पार्टी की सरकार से बड़ी अपेक्षायें थीं—वह अपेक्षा आज धूमिल पड़ रही है ।

हमारे देश में 746 लाख एकड़ में वन है, 22.7 परसेंट एरिये में जंगल लगा हुआ है और बाकी रिवर-वैली के नाम पर, जो हमारे रिफ्यूजी भाई आये उनको बसाने के नाम पर, नये-नये शहरों के बसाने के नाम पर, वनों को उजाड़ा गया । हमारे यहां इतना विशाल वन था, लेकिन उसको काट कर शहरों को बढ़ाया गया । तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने वनों के नाम पर कितना खर्च किया ? आज वनों के बिना वर्षा नहीं हो सकती, वनों के अभाव मे बाढ़ को नहीं रोका जा सकता, वनों के अभाव में उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता, वनों के अभाव में प्रतिरक्षा का काम नहीं हो सकता, वनों के अभाव में संचार का काम नहीं हो सकता और वनों के अभाव में हमारी इण्डस्ट्रीज खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इस पर आपने कितना खर्च किया । पहले प्लान में 9.6 करोड़ रुपया, जो टोटल पब्लिक सेक्टर पर जितना खर्च हुआ—उसका 0.49 परसेन्ट । चौथे प्लान में आपने 92.5 करोड़ रुपया खर्च किया जो टोटल पब्लिक सेक्टर आउट-ले का 0.58 परसेन्ट था ।

अब इस चीज को देखिये कि हमको वनों से आमदनी कितनी होती है, वनों से कागजी आमदनी कितनी होती है ? 1972–73 में स्टेट फारेस्ट डिपार्टमेंट से रायल्टी के रूप में 111.58 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और माइनर-फारेस्ट से प्राप्त हुए थे—50.19 करोड़ रुपये । हम इम्पोर्ट कितना करते हैं ? 1965–66 में जहां पेपर और पेपर बोर्ड के लिए हम 13.48 करोड़ का इम्पोर्ट करते थे— 1974–75 में 58.85 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट किया । उसी तरह से न्यूजप्रिंट जहां 1965–66 में 6.18 करोड का किया था वहां आज 44.99 करोड़ क

[श्री युवराज]

करते हैं। इनसे हमारी आमदनी भी घटती चली गई है। वनों का विस्तार कितना हुआ है इसके आंकड़े भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनके विभाग का यह आकड़ा है, इंडिया 1975 का है। क्लासिफिकेशन आफ टोटल फारेस्ट एरिया 1960–61 म 6 लाख 98 हजार 556 स्क्वेयर किलोमीटर था जो कि 1972–73 में घट कर 4 लाख 49 हजार 389 स्क्वेयर किलोमीटर रह गया। यह वन सम्पदा का हाल है।

देश की इकोनोमी का सब से बड़ा आधार कृषि है, इंडस्ट्री है। दोनों का सम्बन्ध वनों से है। वनों का विस्तार, उनका इम्प्रूवमैंट करने के बजाय दिन प्रति दिन इसमें गिरावट आई है।

वनों के जो अफसर होते है उनके आचरण को आप देखें। संघ लोक सेवा आयोग से फारेस्ट सर्विस में लोग लिये जाते है। क्या उनका करेक्टर होता है इसको आप देखें। गरीब आदमी जो इनके यहां दो रुपये रोज पर काम करता है उनकी कल क्या स्थिति थी और आज क्या हो गई है इसको आप देखें। आपके आसपास तो बहुत सुन्दर वन हैं। इन्हीं लोगों के परिश्रम के बल पर सम्पूर्ण देश और दुनियां खड़ी है और यही वे लोग हैं जों आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गए है ये वे लोग है जो वनों के आस पास रहते हैं। जो कल तक मालिक हुआ करते थे जमीन के वे आज दाने दाने के बिना परेशान है। वनों का विस्तार किये बगैर उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं, उनके बिना कृषि में सुधार नहीं हो सकता है, प्रतिरक्षा का काम नहीं हो सकता हैं, ट्रेनों का आवागमन नहीं हो सकता है। आज स्लीपरों की कमी है। इनको हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। न इम्पोर्ट करें यह दूसरी बात है। लेकिन जरूरत इनको इम्पोर्ट करने की है। मैं कहना चाहता हूं कि 20–30 वर्ष में वनों को इम्प्रूव करके हम अपने देश की इकोनोमी को मजबूत बना सकते थे, वह काम हमने नही किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े उद्योग खोलने की ओर ध्यान दिया, छोटे उद्योगों की उपेक्षा की। वनों पर जो जीने वाले लोग थे उन तमाम गरीब लोगों को परेशान किया गया।

इन शब्दों के साथ और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वनों का विस्तार नहीं किया जाएगा देश की आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी, वनों का विस्तार नही होगा तो देश के उद्योग नही पनपेंगे, विस्तार नही होगा तो हमारी संचार और प्रतिरक्षा व्यवस्था मजबूत नही होगी। इस वास्ते आपका ध्यान अविलम्ब इस ओर जाना चाहिये।

PROF. P. G. MAVLANKAR (Gandhinagar): Mr. Chairman, Sir, I am glad that my friend, Shri Yuvraj brought this half-an-hour discussion on an important subject about which not only we should have continuous discussion but what is more important is that there should be more urgent implementation. As a member of the Board of Management of the Gujarat Agricultural University, for the last four years I have been somewhat closely associated with the problems of agriculture and, also, in particular, with problems of forestry.

Sir, I am distressed to find that the kind of attention one needs to pay to the problem of forests and their development is not being paid. It is truism to say that we are an agricultural counrty. Of course, we know that India is rich in resources but the trouble is that although we are rich in resources, yet we are poor in utilisation of these resources. I should further say that we do not have an integrated, well thought out and continuously well-implemented plan or approach in regard to exploitation of our natural resources including those of forestry. I want Shri Barnalaji to

tell us what the new government are thinking in terms of intensifying not only agriculture in general but forestry in particular. When I say forestry I mean the trees, animals, rainfall, drinking water, climate, etc. When we say potential resources, why are we not paying enough attention to the problem? We seem to slip into short term gains and also to certain kind of commercialising. The manner in which the forests of long duration in our country are removed and got rid of is a colossal and highly unfavourable commentary on the planners and politicians and public men in this country. We feel that we can get certain other advantages, industries and agriculture and other things from the deforestation, some earnings in foreign exchange, private, commercial business, trade, etc. Is this really a sensible thing? Should we not think in terms of both short term commercial and industrial benefits and also long term needs of the agriculture of the country. I feel therefore that afforestation needs to be developed. I cannot say what exactly is the present statistics with regard to afforestation in our country. My suspicion is it is not as high as it ought to be and coming from Gujarat, I can say that the Gujarat percentage is much below the national average.

MR. CHAIRMAN: What is the percentage in Gujarat?

PROF. P. G. MAVALANKAR: You are cross-examining me and if I give you wrong information, it will be a privilege matter! If my memory, however, does not fail, I believe it is between 9 and 11 per cent whereas the national average is 21-22; my impression is that it is less than 12 in Gujarat, almost half the national average. We are way behind. My point is that not only in Gujarat but in other parts of the country also where it is possible, in addition to pumping money, there should be better planning and urgent implementation regarding afforestation.

I was in the Andamans during the emergency period; of course, government did not send me there and I went on my own to see Andamans in one of the intermediate journeys to see the country. I was more than impressed and delighted to see the richness of the forests, the scenary, the climate and everything. Particularly the forest wealth in these islands, there are several hundred islands, is something which you have to see with your own eyes; you cannot imagine it. I should like the hon. Minister to tell us something on that, to tell us how you propose to go ahead with these forests in Andaman Nicobar Islands and in other places in our country.

Wild life is very much part of our forestry and you cannot go about killing animals, because certain part of animal life is also part and parcel of forest life. When you say afforestation it also means preservation of wild life, animal life. I do not believe in rigid memberships of societies for prevention of cruelty to animals. I look at it not from that angle, but from the angle that animals form an inseparable part of forests and we must not neglect them.

18.0 hrs.

Instead of having a narrow, short-term commercially based and quick profit-making approach in these matters, can we not have a long-term approach and see that in order to gain some short-term benefits we do not do damage to our long-term needs of the country, a country of this size, this richness of variety and resourcefulness in agriculture?

I am glad the minister in his original reply said a word about social forestry. I am reminded of a useful seminar held in Ahmedabad, my home town, last year on social forestry. I attended a part of the proceedings of that seminar and I know how useful and fruitful it was. Experts from all over India gave useful ideas. The Minister should tell us whether

[Prof. P. G. Mavalankar]

the government have taken any further action in regard to the fruitful decisions arrived at in that seminar.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): Forests play an important role like agriculture and preservation of forests is vital to the country. I want to ask two questions. In the forest areas, the majority of local population comprises of tribals. Forests were their traditional rights. In 1894 the British Government passed an Act whereby forests were given to the tribals as a right and privilege. In 1952 the Government of India enacted the Forest Act and gave rights and concessions. But at present the government is giving only the concessions but not the rights. I emphasise it because the tribals are exploited by those who go to the forests to exploit the natural resources. Instead of exploiting the natural resources, they exploit the tribals. That is why a working group was set up to study in depth "Tribal Development Programmes based on Forests". They have given about 27 recommendations. I want to know how many of them have been adopted by the Agriculture Ministry and whether the government have given directions to the States to adopt those recommendations. I also want to know what is the present forest policy of the Government of India to protect the tribals from exploitation by those who go there to set up industries or to exploit the natural resources. I request the minister to reply to these two questions.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल एक बात जानना चाहता हूं .....

MR. CHAIRMAN: No, no. I have already called the Minister.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जो अभी वक्तव्य युवराज जी ने और और लोगों ने दिया है उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा, वन नीति और वन सीमा की आड़ में वन विभाग के पदाधिकारी बहुत व्यापक भ्रष्टाचार कर रहे हैं । जंगल के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जिनमें अधिकांश हरिजन, आदिवासी और भूमिहीन लोग हैं, जिन्होंने बीस पच्चीस सालों से जी तोड़ मेहनत कर के उस जमीन को खेती के लायक बनाया है, मैं जानना चाहता हूं क्या उनके साथ उस जमीन का बन्दोबस्त कर दिया जायगा . . . (व्यवधान) . .

दूसरी बात वन सीमा के नाम पर आज क्या हो रहा है ? जिन किसानों का उस भूमि पर कब्जा है, जिनके पास उसके कागजात हैं, उसकी रेन्ट रसीदें हैं उन पर मुकदमे चल रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जमीन छोड़ दी जायगी ?

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वन रोपण के नाम पर जो काम चल रहा है उस में वन रोपण के बजाय वन को उजाड़ने का काम अधिकारी लोग कर रहे हैं । बड़े पैमाने पर वन की लकड़ियां कटवा कर वे लोग बेचवा रहे हैं । डिफारेस्टेशन हो रहा है । तो क्या सरकार उन भ्रष्ट अधिकारियों को निलम्बित या डिस्मिस करने का विचार रखती है ?

PROF. P. G. MAVALANKAR: On a point of order I am very glad my friend in a way was given an opportunity to speak; but I hope what you have done to-day, would not become a precedent, because the rules are very clear on this subject.

MR. CHAIRMAN: The rules do not permit it; and I have not permitted him.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): Mr. Chairman, Sir, I am very glad that my friend Mr. Yuvraj brought in this half-an-hour discussion on this sub-

ject. And some very good suggestions have come from the hon. Members. It is correct, as it has been said, that full and proper attention was not given towards forestry till now. In fact during the last many years, we have seen that there has been denudation of forests, instead of afforestation. There has been spoiling of forests; and lot of damage has been done. Just now, you were hearing two views. One view was: "Some people have cleared some jungles and started cultivation; would you like to take back land from them?" It has been happening so. Some good forests have been taken up by some people; the forest or jungle was cut off from those areas and they were brought under cultivation. Gradually, encroachment occurred in this manner; and forest areas were being spoiled in many States. For public needs also, i.e. whenever there was need for any project or a colony, forest areas were being given; and land in the forest area was given because much money was not needed for it. I received information that 1 lakh hectares of forest area was given every year for this purpose. That is why we have such a thin area of forests. This area is decreasing, as my friend pointed out. In some of the States, the position is actually very bad. For example, the percentage of forest in Gujarat, compared to the geographical area, is only 8.86. This is very low, as compared to the all-India average of 22.8 per cent. That figure is also low; it should be 36 per cent. Mention was made about Andaman-Nicobar Islands. That area is perhaps the best in the whole country. The percentage there is 88.99, i.e., about 90. There are beautiful forests there. Some efforts have been made for social forestry, which has been mentioned by my friend. The National Commission on Agriculture had recommended that schemes for social forestry should be taken up, and schemes were taken up in the five-year plan—only last year. For 1976-77, an amount of Rs. 2.4 crores was spent on social forestry; and the total area was 16,470 hectares that was brought under forests. So, we are trying to improve upon it in a big way. For this year 1977-78, we are increasing it from 16,000 hectares to 62,000 hectares, which is an increase of four times, as compared to the previous year. We are going to spend this year about Rs. 9.50 crores. Next year we are going to increase the area to more than one lakh hectares under social forestry, which means planting of forests in waste lands and panchayat lands and also re-forestation of degraded forests. Some forests have not been completly ruined, but they have been de-graded. Some trees are still standing, but we cannot call them as forests. They have been denuded and they have been cut off. A lot of damage has been done. The damage is more where some urban population is living near that land. They are susceptible to more damage, because some people cut wood from that area, take it to the town and sell it. That is why there are many cases of prosecution. May be, some are genuine cases and not others. According to my friend, some wrong csases have been instituted and they should be withdrawn.

Another proposal that was made was that we should protect the rights of the tribals. I could not understand what rights of the tribals the hon. Member had in mind. Was he referring to their right to cut forests? If so, we are not going to protect those rights. If he was referring to their right to cut, or damage forests, or to cultivate forest land for agricultural purposes, we would not like to protect those rights. But if the tribals want to use the forests to get some income from the forest produce, these poor people are welcome to do that.

The States have also their own schemes in the matter on which the States are spending Rs. 46 crores. The Centre is spending, as I have said, Rs. 9.5 crores.

Afforestation generates a lot of employment. We have calculated

[Shri Surjit Singh Barnala]

that every crore of rupees spent on afforestation gives employment for 10,000 people for the whole year, which means for 150 days in a year.

I think I have covered all the points.

18.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 5, 1977/Agrahayana 14, 1899 (Saka).